नटबर परिदा बिष्णु चरण परिदा बटक्रुष्णा

परिदा बाबाजी परिदा

बनाम

उड़ीसा राज्य

16 अप्रैल, 1975

[पी.एन. एल. अंतवालिया और एस. मुर्तजा फजल अली, जेजे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898, धारा 167 और 344 के तहत अभियुक्त की अभिरक्षा-न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 167 (1), धारा 167 (2), 428 और 484 (2) (ए)-अधिनियम के अनुपालन में लंबित और 60 दिनों की अवधि के भीतर जाँच या अनुसंधान पूरा नहीं किया गया है- अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है।

8 मार्च, 1974 को कटक जिले में एक स्थान पर हुई एक घटना के संबंध में, धारा 147, 148, 307, 302 के तहत किए गए कथित अपराधों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से भी पुलिस जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार किए गए आठ व्यक्तियों में से चार को कटक के सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने चार अपीलार्थियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उप-धारा (2) के परंतुक (ए) के आधार पर उनका प्रतिवाद विद्वान न्यायाधीश द्वारा धारा 484 की उप-धारा (2) के सेंविग धारा (ए) पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने भी उनकी दलील को खारिज कर दिया। यह अपील उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति अनुदत्त करने के आधार पर दायर की गई है।

अभिनिर्धारित किया कि (i) किसी मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाला मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 344 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच विचाराधीनता रहने के दौरान किसी आरोपी को समय-समय पर जेल हिरासत में भेज सकता है। दूसरे शब्दों में, जाँच और साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड की शक्ति प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग था। जांच और आगे के साक्ष्य के संग्रह में सहायता के लिए जब भी आवश्यक हो, इस शक्ति का प्रयोग किया जाना था।{141ई-एफ]

ए. लक्ष्मणराग बनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पार्वतीपुरम और अन्य, [1970] 3 एस.सी.सी. 501 और गौड़ शंकर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1972] 1 एस.सी.सी. 564, पर भरोसा किया।

पश्चिम बंगाल सरकार के कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक बिधीन्द्र कुमार राय और अन्य, एएलआर 1949, कलकत्ता 143; चंद्रदीन दुबे बनाम द स्टेट, 1955 बिहार लॉ जर्नल रिपोर्ट्स 323; दुखी और एक अन्य बनाम राज्य और अन्य, एएलआर 1955 इलाहाबाद, 521: श्रीलाल नंदराम और अन्य, बनाम आर.आर. अग्रवाल, एस.डी.एम. प्रथम श्रेणी, ग्वालियर और एक अन्य कट्टन, ए.आई.आर. 1964, केरल, 232: अर्तत्रन महासुरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, ए.आई.आर. 1956 उड़ीसा, जिसका उल्लेख किया गया हैः

(ii) न्यायालयों के पास कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं होगी। जब तक कानून द्वारा शक्ति प्रदान नहीं की जाती है, तब तक किसी अभियुक्त को किसी भी हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पुरानी संहिता की धारा 344 के संदर्भ के बिना यह मानते हुए गलती की है कि ऐसी शक्ति मौजूद थी। [140डी]:

(iii) नई संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) में विधानमंडल का आदेश है

कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत देता है और उसे 60 दिनों की अवधि से आगे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, भले ही जांच अभी भी चल रही हो। यद्यपि धारा 344 की धारा (1ए) में आने वाली 'उचित कारण' अभिव्यक्ति धारा में कहीं नहीं मिलती है। नई संहिता की धारा 344 के स्पष्टीकरण को उसी भाषा में धारा 309 के स्पष्टीकरण 1 के रूप में बरकरार रखा गया है। नई संहिता की धारा 167 (2) और धारा 309 (2) के परंतुक (2) में जाँच विचाराधीनता रहने के दौरान जेल हिरासत में रिमांड की शक्तियाँ धारा 309 (2) आकर्षित करती है। अपराध का संज्ञान लेने या मुकदमा शुरू होने के बाद ही आगे बढ़ गए हैं। [142 जी-एच]

सवाल -दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 309 के स्पष्टीकरण-1 का उद्देश्य क्या है...?

(iv) धारा 428 के शब्दों के विपरीत, धारा 167 (1) की भाषा जो उप-धारा (2) को भी नियंत्रित करेगी, वह है-"जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है", यह सुझाव देते हुए कि धारा 1973 के अधिनियम के लागू होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी, धारा 428 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति है "जहां एक अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर भेजा गया है", वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए, धारा 484 की उप-धारा (2) का धारा (ए) लागू होगा। अप्रैल, 1974 के पहले दिन से ठीक पहले इस मामले की जांच लंबित थी। अतः कुल (क) को बचाते हुए यह कहा जाता है कि उक्त जाँच पुरानी संहिता के अध्याय XIV के अनुसार जारी रखी जाएगी या की जाएगी। उस संहिता की धारा 167 मजिस्ट्रेट को जांच विचाराधीनता रहने के दौरान अपीलार्थियों को जेल हिरासत में भेजने में सक्षम नहीं बना सकी। पुलिस धारा 344 के तहत जवाबी कार्रवाई करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अदालत की मदद ले सकती है, जिससे अदालत के ध्यान में लाया जा सके कि संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सबूत

प्राप्त किए गए थे कि अपीलार्थियों ने अपराध किया होगा और जब तक रिमांड का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक आगे साक्ष्य प्राप्त करने में बाधा होगी। [143 सी-डी-144 बी-सी]।

श्री बाउचर पियरे आंद्रा, अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली बनाम दिल्ली और अन्य, एएलआर 1975 एस. सी. 164, संदर्भित।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपीलीय संख्या 359/1974।

उड़ीसा उच्च न्यायालय के आपराधिक विविध मामले में विशेष अनुमति द्वारा अपील 1974 का मामला सं. 180 मे पारित निर्णय और आदेश से 6 अगस्त 1974 से।

अपीलकर्ता की ओर से शरद मनोहर, आर. एन. नाथ और वी. एन. गणपुले।

प्रतिवादी के लिए गोबिंद दास और बी. पार्थसारथी।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश ऊंटवालिया के द्वारा सुनाया गया।

8 मार्च 1974 को कटक, उड़ीसा जिले में स्थित एक स्थान पर एक घटना हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट मार्च, 74 को दर्ज की गई थी और धारा 147, 148, 307, 302 के तहत और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से कथित अपराधों के संबंध में पुलिस जांच शुरू की गई थी। विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में चार अपीलार्थियों को पुलिस ने 8 मार्च को जांच के दौरान गिरफ्तार किया था और कटक के सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत पर रिहा किए गए। चार अन्य लोगों को 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें समय-समय पर जेल हिरासत में भेज दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने चार अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन अपीलार्थियों को जमानत देने से इंकार किया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 167 की उप-धारा (2) पर आधारित एक तर्क, जिसे इसके बाद नई संहिता के रूप में संदर्भित किया गया

था, सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 484 की उप-धारा (2) के बचत धारा (ए) पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ताओं ने उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और गुण-दोष के साथ-साथ नई संहिता में उल्लिखित विधि के प्रावधान के आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए अपने मामलों पर दबाव डाला। उच्च न्यायालय की एक पीठ ने 6 अगस्त, 1974 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थियों की ओर से रखी गई दलीलों को खारिज कर दिया है और जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। उन्होंने इस अदालत की विशेष अनुमति से वर्तमान अपील दायर की है।

इस न्यायालय से योग्यता के आधार पर जमानत पर अपीलार्थियों को रिहा करने के प्रश्न की नए सिरे से जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन विचार के लिए सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी नई संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के तहत जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।;

नई संहिता 1 अप्रैल, 1974 को और उससे लागू हुई। धारा 484 (1) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 को निरस्त कर दिया-जिसे इसके बाद पुरानी संहिता कहा जाता है। लेकिन उप-धारा (2) में कुछ सेंविंग खंड उत्कीर्ण किए गए थे; प्रासंगिक धारा को इस निर्णय में इसके बाद जोड़ा जाएगा। ऐसा करने से पहले पुलिस द्वारा किसी मामले की जांच के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड की शक्ति के संबंध में कानून की स्थिति की सराहना करना आवश्यक है।

बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता था जैसा कि पुराने कोडे की धारा 61 में प्रावधान किया गया है। धारा 167 (1) में पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा की गई थी कि यदि धारा 61 द्वारा निर्धारित 24 घंटे की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं

की जा सकी और यदि यह विश्वास करने के लिए आधार थे कि आरोप या सूचना अच्छी तरह से निराधार थी, तो वह अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दे। उप-धारा (2) में प्रावधान किया गया हैः

> "जिस मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत कोई अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है, चाहे उसके पास मामले की सुनवाई करने के लिए अधिकारिता हो या न हो, वह समय-समय पर अभियुक्त को ऐसी हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे। यदि उसके पास मामले की सुनवाई करने या मुकदमे के लिए इसे करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, और वह आगे हिरासत को अनावश्यक समझता है, तो वह आरोपी को ऐसे अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता हैः

जिस मजिस्ट्रेट को आरोपी को भेजा गया था, वह उसे धारा 167 (2) के तहत कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पुलिस हिरासत या जेल हिरासत में भेज सकता है। यहां तक कि जिस मजिस्ट्रेट के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था, वह भी आरोपी को पुरानी संहिता की धारा 167 (2) के तहत 15 दिनों की अवधि से आगे किसी भी हिरासत में नहीं भेज सकता था। ऐसी कोई अन्य धारा नहीं थी जिसने स्पष्ट भाषा में मजिस्ट्रेट को जांच विचाराधीनता रहने के दौरान और आरोप-पत्र जमा करने पर संज्ञान लेने से पहले 15 दिनों की अवधि से आगे रिमांड की यह शक्ति प्रदान की हो। हालांकि, धारा 344 ने मजिस्ट्रेट को किसी भी उचित कारण के लिए किसी भी जांच या मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करने में सक्षम बनाया। पुरानी संहिता की धारा 344 का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः

> "यदि यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त किए गए

हैं कि आरोपी ने कोई अपराध किया है, और यह संभावना है कि रिमांड द्वारा और सबूत प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यह रिमांड के लिए एक उचित कारण है।"

द सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, पश्चिम बंगाल सरकार बनाम बिधिंद्र कुमार रॉय और अन्य (एएलआर 1949, कालूट्टा 143): चंद्रदी दुबे बनाम राज्य (1955 बिहार लॉ जौतनाल की रिपोर्ट 323), दुखी और अन्य बनाम राज्य और अन्य (एएलआर 1955 इलाहाबाद 521); श्रीयल नंदराम और अन्य बनाम आर.आर. अग्रवाल, एस.डी.एम. प्रथम श्रेणी, ग्वालियर और एक अन्य (गेट 1960 मध्य प्रदेश 135) और केरल राज्य बनाम माधवन कुट्टन (ए. एल. आर., 1964, केरल 232) को विचार में लिया गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा अर्तत्रान महासुरा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (एटीआर 1956 उड़ीसा 129) के मामले में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था। यहाँ इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्ति होगी। किसी भी अभियुक्त की अभिरक्षा के लिए कानून द्वारा शक्ति प्रदान आवश्यक है। अपील के तहत आदेश में उच्च न्यायालय ने पुरानी संहिता की धारा 344 के संदर्भ के बिना यह मान लिया है कि ऐसी शक्ति मौजूद थी। यह बात सही नहीं है।

इस न्यायालय के दो निर्णय हैं जो अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचार की पुष्टि करते हैं और ऊपर निर्दिष्ट मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए एक निर्णय पर अधिक निर्णय देते हैं। लक्ष्मणराव वी. वी. न्यायिक-मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पार्वतीपुरम और अन्य ([1970] 3 एसएससी) में एक तर्क दिया कि पुरानी संहिता के अध्याय 24 में धारा 344, जो पूछताछ और परीक्षणों के रूप में सामान्य प्रावधानों का वर्णन करती है, उस मामले पर लागू नहीं हो सकती है जो केवल जांच और साक्ष्य के संग्रह के चरण में था। दुआ, जे डेली द्वारा इस न्यायालय की ओर से पेज 506 निर्णय की पुष्टि करते हुए तर्क को को खारिज कर दिया गया।

"यह तर्क हमें उप-धारा (1-ए) और स्पष्टीकरण दोनों की स्पष्ट भाषा से नकारात्मक प्रतीत होता है। उप-धारा (1-क) के अधीन जाँच या मुक़दमा भी स्थगित किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से पूछताछ शुरू होने से पहले के चरण को संदर्भित करता प्रतीत होता है। स्पष्टीकरण से यह संदेह से परे स्पष्ट हो जाता है कि उप-धारा (1-ए) में उल्लिखित उचित कारण में रिमांड हासिल करके जांच के दौरान और साक्ष्य प्राप्त करने की संभावना शामिल है। धारा 344 की भाषा असंदिग्ध और स्पष्ट है और यह तथ्य कि यह धारा अध्याय 24 में आती है जिसमें सामान्य प्रावधान शामिल हैं पूछताछ और परीक्षण एक तनावपूर्ण स्थिति को उचित नहीं ठहराते हैं।

गौरी शंकर झा बनाम बीकर राज्य और अन्य ([1970] 3 एस.सी.सी) शेलट मामले में न्यायाधीश ने न्यायालय के अध्यक्ष पर निर्णय देते हुए पृष्ठ पर कहा है;

"धारा 167 के तहत आने वाले मामलों में, एक मजिस्ट्रेट निस्संदेह कुल मिलाकर अधिकतम पंद्रह दिनों की अवधि के लिए अभिरक्षा का आदेश दे सकता है और ऐसी अभिरक्षा या तो पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा हो सकती है। दूसरी ओर, धारा 344, अध्याय XXIV में दिखाई देती है जो पूछताछ और परीक्षणों से संबंधित है। इसके अलावा, जिस अभिरक्षा की वह बात करता है, वह ऐसी अभिरक्षा नहीं है जिसे मजिस्ट्रेट धारा 167 के रूप में उचित समझते हैं, बल्कि केवल न्यायिक अभिरक्षा है, जिसका उद्देश्य यह है कि एक बार जांच या मुकदमा शुरू होने के बाद आरोपी को पुलिस के प्रभाव में रहना उचित नहीं है। इस धारा के तहत, मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त व्यक्ति को एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए फिर से हिरासत

में भेज सकता हैं, बशर्ते कि यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हों कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो सकता है और यह संभावना प्रतीत होती है कि रिमांड देकर आगे का सबूत प्राप्त किया जा सकता है।"

विद्वान न्यायाधीश आगे कहते हैं।

"यह तथ्य कि धारा 344 पूछताछ और परीक्षणों से संबंधित अध्याय में आती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उन मामलों पर लागू नहीं होती है जिनमें जांच और साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।"

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि पुरानी संहिता के तहत मजिस्ट्रेट को धारा 344 के तहत किसी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की शक्ति दी गई थी क्योंकि यह धारा उन मामलों में भी लागू होती थी जिनमें जांच और साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया चल रही थी। दूसरे शब्दों में, जाँच और साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड की शक्ति प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग था। इस शक्ति का प्रयोग, जब भी आवश्यक हो, आगे की जांच और संग्रह में सहायता के लिए किया जाना था।

आइए अब नए कोड के तहत विधि की स्थिति की जांच करें। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रख सकता है, जैसा कि पुरानी संहिता की धारा 61 के अनुरूप धारा 57 में उल्लेख किया गया है। धारा 167 के अंतर्गत "पुलिस को सूचना और जाँच करने की उनकी शक्तियाँ" शीर्षक वाले बारहवें अध्याय में कुछ कठोर विचलन किया गया है, जैसा कि पुरानी संहिता के अध्याय चौदह में किया गया है, पुरानी संहिता की धारा 344 के अनुरूप नई संहिता की धारा 309 के संबंध में भी यही स्थिति है-

अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट (निश्चित रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट को नई संहिता के तहत) के पास भेजते हुए, और मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अधिकृत करते हुए, परंतुक (ए) में कहा गया है- इन शब्दों में जोड़ा गया हैः

"बशर्ते कि -

(क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को, पुलिस की अभिरक्षा से भिन्न, पंद्रह दिनों की अवधि के बाद हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत अभिरक्षा में अभियुक्त व्यक्ति को कुल साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, और उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने पर, अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत देता है; और इस धारा के तहत जमानत पर रिहा किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXII के प्रावधानों के तहत इस तरह से रिहा किया गया समझा जाएगा।"

'परंतुक में "मजिस्ट्रेट" पद का अर्थ होगा मजिस्ट्रेट जिसके पास मामले को दबाने का अधिकार क्षेत्र होगा।

"यदि न्यायालय, किसी अपराध या विचारण के प्रारंभ का संज्ञान लेने के बाद, किसी जांच या विचारण के प्रारंभ को स्थगित करना या स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है, तो वह समय-समय पर, दर्ज किए जाने के कारणों से, ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित

समझे, उस समय के लिए, जो वह उचित समझे, स्थगित या स्थगित कर सकता है, और हिरासत में होने पर अभियुक्त को रिमांड पर लेने का आदेशः

यद्यपि धारा 344 की उप-धारा (1ए) में आने वाली 'उचित कारण' अभिव्यक्ति नई संहिता की धारा 309 में नहीं मिलती है, लेकिन पुरानी संहिता की धारा 344 के स्पष्टीकरण को उसी भाषा में धारा 309 के स्पष्टीकरण 1 के रूप में बरकरार रखा गया है। नई संहिता की धारा 167 (2) और धारा 309 (2) के परंतुक (ए) में उत्कीर्ण कानून जांच विचाराधीनता रहने के दौरान जेल अभियुक्त को रिमांड की शक्तियां प्रदान करता है। धारा 309 (2) किसी अपराध का संज्ञान लेने या मुकदमा शुरू होने के बाद ही लागू होती है। ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण का उद्देश्य क्या है [धारा 309 में स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर परंतुक (क) में विधानमंडल का आदेश है कि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत देता है और उसे 60 दिनों की अवधि से आगे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, भले ही जांच अभी भी चल रही हो। आपराधिक हठधर्मिता के गंभीर अपराधों-हत्या, डकैती, अंतर-राज्यीय गिरोहों द्वारा डकैती या इस तरह के मामलों में, पुलिस के लिए इन परिस्थितियों में यह संभव नहीं हो सकता है। जैसा कि वे हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, 60 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करने के लिए। फिर भी विधायिका का इरादा अदालत को कोई विवेकाधिकार नहीं देना और आरोपी को जमानत पर रिहा करना उसके लिए अनिवार्य बनाना प्रतीत होता है। बेशक, परंतुक (ए) में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 167 के तहत जमानत पर रिहा किए गए आरोपी को अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत और उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए इस तरह से रिहा किया गया माना जाएगा। यह न्यायालय को उसे जमानत पर रिहा करने का अधिकार दे सकता है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो यह निर्देश देने के

लिए कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और अध्याय में आने वाली धारा 437 की उप-धारा (5) में प्रावधान के अनुसार हिरासत में लिया जाए। यह भी स्पष्ट है कि संज्ञान लेने के बाद रिमांड की शक्ति का प्रयोग नई संहिता की धारा 309 के तहत किया जाना है। लेकिन अगर 60 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है तो गंभीर और भयावह प्रकार के अपराधों में भी आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा। इस तरह का कानून "अपराधियों के लिए स्वर्ग" हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अदालतों के कारण ऐसा नहीं होगा, जैसा कि कभी-कभी माना जाता है। यह विधानमंडल के आदेश के तहत होगा।

लेकिन इस मामले में सवाल यह है कि क्या नई संहिता के लागू होने से पहले शुरू हुई जांच विचाराधीनता रहने के दौरान अपीलार्थी उस संहिता की धारा 167 (2) के सेवा परंतुक (ए) पर दबाव डाल सकते हैं और जमानत देने के लिए तैयार होने पर अधिकार के मामले के रूप में जमानत पर रिहा होने का दावा कर सकते हैं।इस प्रश्न का उत्तर नई संहिता की धारा 167 और 484 की व्याख्या पर निर्भर करता है।धारा 428 के शब्दों के विपरीत धारा 167 (1) की भाषा जो उप-धारा (2) को भी नियंत्रित करेगी, "जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है", यह सुझाव देती है कि जब अधिनियम के लागू होने के बाद गिरफ्तारी की जाती है तो धारा का उल्लेख किया जाएगा। जबकि धारा 428 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति है "जहां एक प्रति-पुत्र अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने पर सजा सुनाई गई है।" इस तरह के वाक्यांश की व्याख्या करते हुए यह श्री बाउचर पियरे एंड्रा बनाम स्टपेरिन के मामले में आयोजित किया गया है - वादी, केंद्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली और एक अन्य (*) भगवती, जे. द्वारा पृष्ठ 166 पर इस न्यायालय का निर्णय देते हुए:

"यह धारा, अपनी भाषा के एक सादे स्वाभाविक निर्माण पर,
तथ्य स्थिति की इसकी प्रयोज्यता के लिए प्रस्तुत करता है जो धारा

द्वारा वर्णित है "जहां एक अभियुक्त व्यक्ति के पास है, दोषसिद्धि पर, एक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई।' इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से सुझाव देता है कि दोषसिद्धि और सजा नई दंड प्रक्रिया संहिता के लागू होने के बाद होनी चाहिए...?'

हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि धारा 167 (1) में आने वाले वाक्यांश "गिरफ्तार किया गया है" के बावजूद, चूंकि पुरानी संहिता को नई संहिता की धारा 484 की उप-धारा (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इसलिए यह प्रावधान लागू होता, यदि बचत में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: उप-धारा (2) उस स्थिति पर लागू नहीं होती जिससे हम इस मामले में संबंधित हैं। हमारे निर्णय में धारा 484 की उप-धारा (2) का धारा (ए) लागू होता है। वह इस प्रकार हैः

"इस तरह के निरसन के बावजूद, -

(क) यदि, इस संहिता के लागू होने की तारीख से तुरंत पहले, कोई अपील, आवेदन, विचारण, पूछताछ या जांच लंबित है, तो ऐसी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या जांच का निपटान, जारी रखा जाएगा, आयोजित किया जाएगा या किया जाएगा, जो भी मामला हो, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के प्रावधानों के अनुसार, जो इस तरह के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू था (जिसे इसके बाद पुरानी संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है), जैसे कि यह संहिता लागू नहीं हुई थीः"

अप्रैल, 1974 के पहले दिन से ठीक पहले इस मामले की जांच लंबित थी। अतः बचत धारा (क) में आदेश दिया गया है कि उक्त जांच जारी रखी जाएगी या पुरानी संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।इसलिए, जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी

को पुरानी संहिता के अध्याय XIV के अनुसार इसे जारी रखना और पूरा करना होगा। उस संहिता की धारा 167 मजिस्ट्रेट को जाँच विचाराधीनता रहने के दौरान अपीलार्थियों को जेल हिरासत में भेजने में सक्षम नहीं बना सकी।पुलिस धारा 344 के तहत रिमांड की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अदालत की मदद ले सकती है, जिससे यह अदालत के ध्यान में लाया जा सके कि यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त किए गए हैं कि अपीलकर्ताओं ने कोई अपराध किया हो सकता है और जब तक रिमांड का आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक आगे के सबूत प्राप्त करने में बाधा होगी।जैसा कि हमने ऊपर कहा है, जांच अधिकारी द्वारा पुरानी संहिता की धारा 344 के तहत अदालत की शक्ति का उपयोग करना जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा होगा जिसे जारी रखा जाना है और पुरानी संहिता के अनुसार किया जाना है।ऐसा होने पर, हमारा मानना है कि इस मामले में अपीलकर्ता नई संहिता की धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के बिना जारी किए जाने का दावा नहीं कर सकते हैं।

परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

वी.एम.बी.के.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।